सम्पादकीय

सशक्त हों जिला अस्पताल

राज्य गठन के 17 साल बाद भी जिला अस्पतालों में बदहाली बरकरार है। अभी भी संसाधनों और चिकित्सकों के अभाव में कई जिला अस्पतालों में सर्जरी नहीं होती। कुछ जिला अस्पतालों में दिन में तो सर्जरी होती है लेकिन रात में नहीं। वहां सर्जरी की सुविधा नहीं होने से मरीजों को रिम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों को रेफर कर दिया जाता है। इससे जहां मेडिकल कॉलेजों पर भार बढ़ जाता है, वहीं इसका असर मातृ मृत्यु दर पर भी पड़ता है। प्रसव में जटिलता आने पर वहां सर्जरी नहीं हो पाती और चिकित्सक अंतिम समय में गर्भवती महिलाओं को रिम्स या दूसरे मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। इससे कई बार महिलाओं या नवजात की मौत रास्ते में ही हो जाती है। अब राज्य का स्वास्थ्य विभाग सभी जिला अस्पतालों को सशक्त कर वहां चौबीसों घंटे सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो मरीजों के हित में यह बहुत बड़ा काम होगा। जिला अस्पतालों में ही सर्जरी से प्रसव सुनिश्चित करने पर महिलाओं को रिम्स या अन्य मेडिकल कॉलेज रेफर करने की समस्या नहीं रहेगी। इसमें कई चुनौतियां भी होंगी। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उन चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता होगी। राज्य में बार-बार प्रयास के बावजूद आवश्यक संख्या में ऐसे चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने पर सेवानिवृत्त या निजी चिकित्सकों की सेवा ऑन कॉल लेने की भी स्वीकृति दी है। लेकिन इसके लिए अस्पतालों को आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध करानी होगी। इन अस्पतालों में सर्जरी नहीं होने का एक बड़ा कारण वहां ब्लड बैंक नहीं होना है। हालांकि विभाग आठ जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक को एक-दो माह में क्रियाशील करने की दिशा में भी काम कर रहा है। जिला अस्पतालों को पहले भी चिकित्सीय उपकरणों से लैस करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन सिविल सर्जनों की लापरवाही से इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पाया। कहीं तकनीशियन की कमी से एक्सरे मशीन धरी रह गई तो कहीं ये घपले-घोटाले की भेंट चढ़ गई। जबतक जिला अस्पतालों में योग्य, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिविल सर्जनों तथा उपाधीक्षकों का पदस्थापन नहीं होगा, तबतक यह समस्या बनी रहेगी। सरकार को ऐसे चिकित्सा पदाधिकारियों की पहचान कर उन्हें जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है।

संयम जरूरी

फगवाड़ा में शुक्रवार देर रात दो गुटों में हुए टकराव के बाद शनिवार को पूरे क्षेत्र में उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह टकराव किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता। इससे कई आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं और सूबे की शांति भंग होने का डर एक बार फिर पैदा हो गया है। सांप्रदायिक सौहार्द जब भी बिगड़ता है, किसी का भी भला नहीं होता। यह चिंताजनक है कि शुक्रवार रात की घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती रहीं और नतीजा यह हुआ कि शनिवार को लुधियाना-जालंधर हाईवे पर पुलिस को ही एहतियातन ट्रैफिक को रोकना पड़ा, आवाजाही करने वाले लोगों के सचेत करना पड़ा या फिर उन्हें कोई और रूट लेने की सलाह देनी पड़ी। हजारों लोगों को एक बार फिर परेशान होना पड़ा। मामला कोई भी हो, वह जायज है या नहीं, यह अलग बात है लेकिन उसे लेकर प्रदर्शन करने के लिए सही तरीका अपनाया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही हालांकि सरकार ने स्वयं ही सभी सरकारी संस्थानों में छुट्टी कर दी थी और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी एहियातन खुद ही बंद रहे लेकिन फिर भी सड़कों पर आम जन की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही होने चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। पता नहीं कोई इस वजह से इलाज के लिए अस्पताल, कोई परीक्षा देने केंद्र तक, कोई जरूरी कार्यवश यात्र के लिए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक न पहुंच पाए। इस तरह से सोचना चाहिए कि इन परेशान होने वालों में न जाने हमारा ही कोई परिचित, दोस्त या रिश्तेदार हो तो.. ? ऐसे अवसर बड़े नाजुक होते हैं और इनमें संयम बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश पहले कई बार पंजाब में हालात काफी खराब हो चुके हैं। पूर्व की उन घटनाओं से सबक लेना चाहिए। पुलिस व प्रशासन को भी चाहिए कि वह स्थिति से निपटने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाए। प्रदर्शनकारी समुदायों को समझाया जाना चाहिए। केवल इंटरनेट सेवाएं ठप कर देना या खुद ही प्रतिष्ठान बंद करवा समस्या को हल कर देना सही तरीका नहीं कहा जा सकता।

आशा वर्मा

सुरक्षा का मोर्चा

भारत को हथियार और रक्षा संबंधी साजो-सामान निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं वे महत्त्वपूर्ण तो हैं ही, वक्त की जरूरत को भी रेखांकित करते हैं।

भारत को हथियार और रक्षा संबंधी साजो-सामान निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं वे महत्त्वपूर्ण तो हैं ही, वक्त की जरूरत को भी रेखांकित करते हैं। चेन्नई में रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की तीनों सेनाओं को और सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन और खरीद प्रक्रिया में नीतिगत बदलाव लाने का जो संकेत दिया है उससे सरकारी, निजी और विदेशी कंपनियों को समान अवसर मिल सकेंगे। इससे देश में ही रक्षा साजो-सामान बनाने के लिए तीनों क्षेत्रों की कंपनियां प्रतिस्पर्धी बन कर उतर सकेंगी। भारत अपने लिए तो छोटे-बड़े हथियार बनाएगा ही, अब दूसरे देशों के साथ भागीदारी कर उनके लिए भी रक्षा क्षेत्र में काम भी करेगा। रक्षा प्रदर्शनी में पांच सौ भारतीय और डेढ़ सौ विदेशी कंपनियों की शिरकत इस बात का सबूत है कि भारत रक्षा बाजार बनने की दिशा में बढ़ चुका है। अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तो एफ-16 लड़ाकू विमान निर्माण का काम भारत लाने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा जैवलिन मिसाइल बनाने की तकनीक भी भारत को हासिल हो सकती है। यह सामरिक और कारोबारी दृष्टि से भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।भारत के लिए देश में ही हथियारों और रक्षा उत्पादों का निर्माण इसलिए जरूरी हो गया है कि सीमा पर तैनात जवानों को लंबे समय से छोटे हथियारों की कमी से जूझना पड़ रहा है। चार हजार किलोमीटर लंबी सीमा और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां चिंता का विषय हैं। डोकलाम की घटना के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। पाकिस्तान के साथ भी भारतीय सीमा काफी लंबी है और सीमा पार आतंकवाद की वजह से यहां तैनात जवानों को छोटे हथियारों की सख्त जरूरत है। हालांकि कुछ महीने पहले ही रक्षामंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद समिति ने करीब सोलह हजार करोड़ रुपए की खरीद को हरी झंडी दी है।सैनिकों के संख्या बल और हथियारों के जखीरे के हिसाब से चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत की सेना आती है। ऐसे में यह गंभीर सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद हमारे जवानों के पास आधुनिक हथियार क्यों नहीं हैं। क्यों उन्हें पुराने घिसे-पिटे हथियारों से लड़ना पड़ रहा है? रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति भी सेना में हथियारों की कमी पर चिंता जता चुकी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि सेना का अड़सठ फीसद साजो-समान संग्रहालय में रखने लायक हो गया है। केवल चौबीस फीसद साजो-समान इस्तेमाल करने लायक है। सेना के पास मात्र आठ फीसद ऐसे हथियार और उपकरण हैं, जिन्हें पूरी तरह अत्याधुनिक कहा जा सकता है। इसकी असल वजह सेना का एक तरह से खजाना खाली होना है। जरूरत के हिसाब से सेना को जितना बजट मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इसका सीधा असर सेना के आधुनिकीकरण पर पड़ रहा है। सेना की सवा सौ परियोजनाओं के लिए उनतीस हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। नई योजनाओं के लिए खजाना खाली है। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत पच्चीस परियोजनाएं हैं, लेकिन उन पर काम करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। ऐसे में गंभीर सवाल है कि अगर सेना के पास पर्याप्त पैसा ही नहीं होगा तो कैसे रक्षा परियोजनाएं सिरे चढ़ पाएंगी और कैसे हम अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा पाएंगे!

मनजीत सिंह

ज्ञान-विज्ञान

ना सुन पाने वालों के लिए

बहरेपन से ग्रसित लोगों में से लगभग 50 प्रतिशत लोगों में बहरापन इसी वजह से होता है। बहरेपन के शिकार लोगों में डीएनए की पूरी लंबाई में 300 से भी ज्यादा ऐसे स्थान पाए गए हैं जो इस मामले में प्रासंगिक हैं। सौ से भी अधिक ऐसे जीन्स पृथक किए गए हैं जिनके बारे में लगता है कि वे बहरेपन के लिए जिम्मेदार हैं। जीन डीएनए का एक खंड होता है जो किसी खास प्रोटीन बनाने की सूचना संजोए रखता है। जीन उपचार से इस स्थिति का इलाज संभव है। जीन उपचार में गड़बड़ जीन को, स्वस्थ उपचारात्मक जीन से बदल दिया जाता है ताकि प्रभावित या गड़बड़ कोशिका ज़रूरी प्रोटीन बना सके और ठीक से काम कर सके।

दुनिया भर में लगभग ढाई करोड़ लोग बहरेपन से ग्रसित हैं। इनमें लगभग 50 प्रतिशत लोगों के बहरेपन का कारण वंशानुगत गड़बड़ी है। इनमें से ज्यादातर मामलों में कान के श्रवण अंग की कार्य-प्रणाली प्रभावित होती है। जिसमें कोई भी चिकित्सीय उपचार कारगर नहीं होता। सुनने की क्षमता में आंशिक रुप से सुधार के लिए कान में श्रवण यंत्र लगाए जाते हैं या फिर कान के मध्य या भीतरी भाग में प्रत्यारोपण भी किया जाता है। इक्षकतु यह हमेशा संभव नहीं होता।

कई बीमारियों जैसे हिमोफीलिया, ल्यूकेमिया और पार्किसंस का उपचार जीन उपचार से संभव हुआ है। इस उपचार में जीवित कोशिका में जेनेटिक पदार्थ

प्रत्यारोपित करके प्रभावित अंग की कार्यप्रणाली में बदलाव किया जाता है। जीन थेरपी से बहरेपन के उपचार की कुछ सीमाएं हैं क्योंकि सुनने की प्रक्रिया में कान के एक से अधिक हिस्से शामिल होते हैं। खास तौर पर भीतरी और बाहरी रोम कोशिकाएं इस प्रक्रिया में परस्पर तालमेल से काम करते हुए स्तनधारियों के कान को ज़बरदस्त संवेदनाओं से लैस करती हैं। मैसाचुसेट्स, शिकागो, न्यू ओरलीएन्स, नॉर्थ कैरोलिना, वाड्क्षशगटन और विएना के संस्थानों में कार्यरत शोधकर्ताओं के दो समूहों ने नेचर बायोटेक्नालॉजी पत्रिका में बताया है कि उन्होंने प्रयोगशाला में एक ऐसा वायरस बनाने में सफलता हासिल कर ली है जो भीतरी कान की कोशिका में घुसकर जेनेटिक पदार्थ का एक टुकड़ा वहां रोपित कर सकता है। इस जेनेटिक पदार्थ के रोपण के बाद दोनों तरह की कमज़ोर रोम कोशिकाओं को ठीक किया जा सकता है। यह प्रयोग माउस (एक किस्म के चूहे) को प्रभावित करने वाली, भीतरी कान की एक खास तकलीफ पर किया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह पहली बार है कि श्रवण क्षमता को बहाल किया जा सका है और यह मनुष्यों में बहरेपन के उपचार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।यह सही है कि कान की बनावट ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने और उसे आगे पहुंचाने का ढांचा उपलब्ध कराती है इक्षकतु ध्वनि तरंगों को तंत्रिका संकेतों में बदलने का काम भीतरी कान में रोम-समान संरचनाएं करती हैं। ध्वनि की पहचान इन्हीं तंत्रिका संकेतों से होती है। अलग-अलग रोम कोशिकाएं उच्च और निम्न आवृत्ति की (पतली और मोटी) ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होती हैं। अन्य रोम कोशिकाएं अलग-अलग आवृत्ति की ध्वनियों को एक खास जगह केन्द्रित करने में मदद करती हैं। कान की पूरी रचना अविश्वसनीय रूप से जटिल होती है। कान में एक छोटा-सा तरल-भरा अनुकंपन कक्ष, कॉक्लिया, होता है। इसमें दसियों हज़ार रोम कोशिकाएं होती हैं। ध्वनि की विभिन्न आवृत्तियां अलग-अलग इक्षबदुओं पर केंद्रित होती हैं और ये इक्षबदु एक-दूसरे से मिलीमीटर के सौंवें हिस्से से भी कम दूरी पर स्थित होते हैं।

शरीर की विभिन्न क्रियाओं का तालमेल प्रोटीन की सक्रियता से बनता है। विभिन्न प्रोटीन हमारे अंगो को खास तरीके से काम करने के लिए संकेत देते हैं। कोशिका में अमीनो अम्ल नामक इकाइयों को अलग-अलग क्रम में जोड़कर हजारों प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अमीनो अम्लों का यह क्रम डीएनए की लंबाई में मौजूद अनुक्रम से निर्धारित होता है। डीएनए वह विशाल अणु है जिसमें कोशिका की संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी कूटबद्ध रहती है। यदि किसी कोशिका के कार्य के लिए ज़रूरी प्रोटीन के कोड में कोई गलती या चूक हो जाती है तो वह कोशिका उस प्रोटीन को बनाने में समर्थ नहीं होती। जिसके परिणामस्वरूप कोशिका ठीक तरह से काम नहीं कर पाती।बहरेपन से ग्रसित लोगों में से लगभग 50 प्रतिशत लोगों में बहरापन इसी वजह से होता है। बहरेपन के शिकार लोगों में डीएनए की पूरी लंबाई में 300 से भी ज्यादा ऐसे स्थान पाए गए हैं जो इस मामले में प्रासंगिक हैं। सौ से भी अधिक ऐसे जीन्स पृथक किए गए हैं जिनके बारे में लगता है कि वे बहरेपन के लिए जम्मेदार हैं। जीन डीएनए का एक खंड होता है जो किसी खास प्रोटीन बनाने की सूचना संजोए रखता है। जीन उपचार से इस स्थिति का इलाज संभव है। जीन उपचार में गड़बड़ जीन को, स्वस्थ उपचारात्मक जीन से बदल दिया जाता है ताकि प्रभावित या गड़बड़ कोशिका ज़रूरी प्रोटीन बना सके और ठीक से काम कर सके।

आलेख

निरंकार सिंह

जैसे-जैसे हिन्दू राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद होती जा रही है उसके समक्ष यह समस्या भी उत्पन्न हो रही है कि वह दलितों की सामाजिक न्याय पाने की महत्वाकांक्षा से कैसे निपटे। हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति, जाति और लैंगिक पदक्रम पर आधारित है। इस पदक्रम का समर्थन आरएसएस चिंतक व संघ परिवार के नेता करते आ रहे हैं। उनके सामने समस्या यह है कि वे इन वर्गों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं करना चाहते परंतु चुनावों में उनके वोट प्राप्त करना चाहते हैं। इसी कारण वे एक ओर दलितों के नायक बाबा साहब अंबेडकर को अपना सिद्ध करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी ओर, दलितों को अपने झंडे तले लाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि दलित, भगवान राम और पवित्र गाय पर आधारित उनके एजेंडे को स्वीकार करें।

अंबेडकर के नाम में 'रामजी' पर जोर

इन दिनों कई दलित संगठन, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा उसके आधिकारिक अभिलेखों में भीमराव अंबेडकर के नाम में 'रामजी; शब्द जोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। यह सही है कि संविधान सभा की मसविदा समिति के अध्यक्ष बतौर, अंबेडकर ने संविधान की प्रति पर अपने हस्ताक्षर, भीमराव रामजी अंबेडकर के रूप में किए थे। परंतु सामान्यतः, उनके नाम में रामजी शब्द शामिल नहीं किया जाता है। तकनीकी दृष्टि से उत्तरप्रदेश सरकार के इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती परंतु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह निर्णय, अंबेडकर को अपना घोषित करने की हिन्दुत्ववादी राजनीति का हिस्सा है। भाजपा के लिए भगवान राम, तारणहार हैं। उनके नाम का इस्तेमाल कर भाजपा ने समाज को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत किया- फिर चाहे वह राममंदिर का मुद्दा हो, रामसेतु का या रामनवमी की पूर्व संध्या पर जानबूझकर भड़काई गई हिंसा का। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से हम भारत में दो विरोधाभासी प्रवृत्तियों का उभार देख रहे हैं। एक ओर दलितों के विरूद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर, अंबेडकर की जयंतियां जोर-शोर से मनाई जा रही हैं और हिन्दू राष्ट्रवादी अनवरत अंबेडकर का स्तुतिगान कर रहे हैं।

इस सरकार के पिछले लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में हमने दलितों के दमन के कई उदाहरण देखे। आईआईटी मद्रास में पेरियार स्टडी सर्किल पर प्रतिबंध लगाया गया, रोहित वेमूला की संस्थागत हत्या हुई और ऊना में दलितों पर घोर अत्याचार किए गए। मई 2017, जब योगी आदित्यनाथ उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, में सहारनपुर में हुई हिंसा में बड़ी संख्या में दलितों के घर जला दिए गए। दलित नेता चंद्रशेखर रावण, जमानत मिलने के बाद भी जेल में हैं क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई। दलितों के घरों को आग के हवाले करने की घटना, भाजपा सांसद के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस के बाद हुई जिसमें %यूपी में रहना है तो योगी-योगी कहना होगा% व %जय श्रीराम% के नारे लगाए जा रहे थे। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में दलितों के खिलाफ हिंसा भड़काई गई और जैसा कि दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने कहा है, हिंसा भड़काने वालों के मुख्य कर्ताधर्ता भिड़े गुरुजी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाजपा की केन्द्र सरकार में मंत्री व्हीके सिंह ने सन् 2016 में दलितों की तुलना कुत्तों से की थी और हाल में एक अन्य केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने भी ऐसा ही कहा। उत्तरप्रदेश के कुशीनगर में जब योगी आदित्यनाथ मुशहर जाति के लोगों से मिलने जा रहे थे, उसके पूर्व अधिकारियों ने दलितों को साबुन की बट्टियां और शैम्पू बांटे ताकि वे नहा-धोकर साफ-सुथरे लग सकें।

मोदी-योगी मार्का राजनीति की मूल नीतियों और चुनाव में अपना हित साधने की उसकी आतुरता के कारण यह सब हो रहा है। सच यह है कि मोदी-योगी और अंबेडकर के मूल्यों में मूलभूत अंतर है। अंबेडकर, भारतीय राष्ट्रवाद के हामी थे। वे जाति का उन्मूलन करना चाहते थे और उनकी यह मान्यता थी कि जाति और अछूत प्रथा की जड़ें हिन्दू धर्मग्रंथों में हैं। इन मूल्यों को नकारने के लिए अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो स्वाधीनता संग्राम के वैश्विक मूल्यों पर आधारित था। भारतीय संविधान के आधार थे समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल्य। दूसरी ओर थीं हिन्दू महासभा जैसी संस्थाएं, जिनकी नींव हिन्दू राजाओं और जमींदारों ने रखी थी और जो भारत को उसके %गौरवशाली अतीत% में वापस ले जाने की बात करती थीं- उस अतीत में जब वर्ण और जाति को ईश्वरीय समझा और माना जाता था। हिन्दुत्ववादी राजनीति का अंतिम लक्ष्य आर्य नस्ल और ब्राह्मणवादी संस्कृति वाले हिन्दू राष्ट्र का निर्माण है। आरएसएस इसी राजनीति का पैरोकार है।माधव सदाशिव गोलवलकर व अन्य हिन्दू चिंतकों ने अंबेडकर के विपरीत, हिन्दू धर्मग्रंथों को मान्यता दी। सावरकर का कहना था कि मनुस्मृति ही हिन्दू विधि है। गोलवलकर ने मनु को विश्व का महानतम विधि निर्माता निरूपित किया। उनका कहना था कि पुरुषसूक्त में कहा गया है कि सूर्य और चन्द्र ब्रह्मा की आंखें हैं और सृष्टि का निर्माण उनकी नाभि से हुआ। ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण उपजे, उनके हाथों से क्षत्रिय, उनकी जंघाओं से वैश्य और उनके पैरों से शूद्र। इसका अर्थ यह है कि वे लोग जिनका समाज इन चार स्तरों में विभाजित है, ही हिन्दू हैं।

भारतीय संविधान के लागू होने के बाद, आरएसएस के मुखपत्र आर्गनाईजर ने अपने एक संपादकीय में संविधान की घोर निंदा की।

आरएसएस, लंबे समय से कहता आ रहा है कि भारतीय संविधान में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हाल में केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने भी यही बात कही। जब अंबेडकर ने संसद में हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत किया था, तब उसका जबरदस्त विरोध हुआ था। दक्षिणपंथी ताकतों ने अंबेडकर की कड़ी निंदा की थी। परंतु अंबेडकर अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा, %तुम्हें न केवल शास्त्रों को त्यागना चाहिए बल्कि उनकी सत्ता को भी नकारना चाहिए, जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। तुम में यह साहस होना चाहिए कि तुम हिन्दुओं को यह बताओ कि उनमें जो गलत है वह उनका धर्म है- वह धर्म, जिसने जाति की पवित्रता की अवधारणा को जन्म दिया है।%

आज क्या हो रहा है? आज अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा को औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष वाई. सुदर्शन ने हाल में कहा था कि इतिहास में किसी ने जाति प्रथा के विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं की और इस प्रथा ने हिंदू समाज को स्थायित्व प्रदान किया। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करना और विश्वविद्यालयों में इन वर्गों व ओबीसी के लिए पदों में आरक्षण संबंधी नियमों में बदलाव, सामाजिक न्याय और अंबेडकर की विचारधारा पर सीधा हमला है।

जैसे-जैसे हिन्दू राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद होती जा रही है उसके समक्ष यह समस्या भी उत्पन्न हो रही हैं